Title: Situation arising out of non-involvement of National Centre for Promotion of Employment for Disabled in formulation of policy for them.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : महोदय, विकलांगों के लिए सरकार ने राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया है। यह मसौदा किसी भी तरह से विकलांगों के हित में नहीं है। नेशनल सेन्टर फॉर प्रमोशन आफ एम्प्लायमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपुल ने इस नीति को ठुकरा दिया है। दस वर्षों तक लटकाने के बाद विकलांगों के लिए यह नीति बनाई गयी और इस नीति को बनाने से पहले विकलांगों से सम्बन्धित संस्थाओं से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया। यह जो मसौदा बनाया गया, न इसे प्रचारित किया गया और न लोगों के सुझाव आमन्त्रित किए गए। इस मसौदे को देखकर लगता है जैसे दयाभाव की भावना इसमें दर्शायी गयी हो।

सभापति महोदय, यह करोड़ों विकलांगों की भावना से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आवश्यकता इस बात की है कि विकलांग दयाभाव के पात्र न बनें, वे आत्मनिर्भर बनें और उसी को आधार मान कर सरकार को विकलांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करना चाहिए था। इसकी जानकारी अचानक वेबसाइट पर दी गई है लेकिन इसे प्रचारित नहीं किया गया है। यह बहुत गम्भीर मामला है। सरकार जानबूझ कर ऐसा प्रयास कर रही है, विकलांगों के हित के लिए जो नीति बननी चाहिए, उसमें उनके सुझावों की भागीदारी न हो, उनके सुझाव आमंत्रित न किए जाएं, पूरे देश में इस पर चर्चा न हो। किसी भी कीमत पर यह मसौदा और नीति न्यायसंगत नहीं हो सकती। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विकलांगों के लिए जो राष्ट्रीय नीति बन रही है, उसमें विकलांगों की भावनाओं का समावेश हो। वह पूरे देश में प्रचारित हो, पूरे देश में बहस की जाए और इसके बाद इनके लिए कोई नीति बने। मुझे यही निवेदन करना था। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Chandra Shekhar Dubey − Not present.